आठ से बंद रखेंगे गत्ता उद्योग

बद्दी में उत्पादकों ने पेपर मिल मालिकों के खिलाफ खोला मोर्चा

निजी संवाददाता, बद्दी

उत्तरी राज्यों के गत्ता उत्पादकों की अपनी मांगों को लेकर बद्दी में बैठक हुई। इसमें पेपर मिल मालिकों के खिलाफ मोर्चा खोलने का निर्णय लिया गया। इस बैठक में हिमाचल के अलावा पंजाब, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, गुजरात, यूपी, उत्तराखंड व चंडीगढ़ के 300 से ज्यादा गत्ता उत्पादकों ने भाग लिया। बैठक में कहा गया कि पेपर मालिकों द्वारा पेपर का बीस फीसदी रेट बढ़ा देने से पंजाब और हिमाचल के सैकड़ों गत्ता उत्पादक छह दिन की सांकेतिक हड़ताल पर जाएंगे। संयुक्त संघर्ष समिति के चेयरमैन व पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हरीश मदान, पंजाब इकाई के प्रधान आरपी सिंह, हिमाचल चैप्टर के प्रधान देवेंद सहगल, उपाध्यक्ष मुकेश जैन व सुरेंद्र जैन ने बताया कि उन्होंने आठ से 13 मार्च तक हिमाचल व पंजाब के सभी गत्ता उद्योग बंद रखने का निर्णय लिया है। इस दौरान पेपर मिलों से किसी भी प्रकार का लेन-देन नहीं किया जाएगा। हड़ताल के दौरान किसी भी अन्य कारखाने को पेटियां सप्लाई नहीं की जाएंगी और न ही अन्य प्रदेशों से

बद्दी : गत्ता उत्पादकों की बैठक में उपस्थित विभिन्न राज्यों के पदाधिकारी

पेपर अंदर आने दिया जाएगा। गुस्साए उद्योग नेताओं ने कहा कि उन्हें बार-बार पेपर मिलों की ओर से जलील किया जा रहा है और मनमाने रेट थोपे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे हड़ताल नहीं करना चाहते और उनका उद्देश्य अपने वेंडर व उपभोक्ताओं को परेशान करना नहीं, बल्कि मिल मालिकों की कथित दादागिरी के प्रति आंखें खोलना है। उन्होंने कहा कि पिछले दो साल से उत्तरी राज्यों के मिल मालिकों ने पेपर के दामों में आशातीत वृद्धि की है। मुकेश जैन ने कहा कि मिल मालिक हर 15 दिन बाद पेपर का रेट बढ़ा देते हैं और जब हम बढ़े हुए रेटों के हिसाब से अपने उपभोक्ताओं को

देश भर के 300 कारोबारियों का फैसला

कहते हैं, तो वे उसें पर विचार को कहते हैं। जब तक हमारा उस पर विचार कर रहा होता है तक पेपर मिल मालिक और रेट बढ़ा देते हैं। महासचिव सुरें ने कहा कि पेपर मिल मालिक में जान-बूझकर पांच दिन अपनी बंद रखते हैं। पूर्व राष्ट्रीय प्रधान उत्पादक संघ हरीश मदान ने कि इससे पहले हम सभी सात मिलकर तीन मार्च को जंतर-मं आगे भारी संख्या में जुटेंगे औ पर प्रदर्शन करेंगे।

कार्टन फैक्टरी बंद होने के लिए वीरभद्र जिम्मेदार : बरागटा

शिमला, 28 फरवरी (निस)। बागवानी मंत्री नरेन्द्र बरागटा ने शिमला जिला की कोटखाई तहसील के अंतर्गत गुम्मा स्थित कार्टन फैक्टरी को बंद करने के संदर्भ में केन्द्रीय इस्पात मंत्री वीरभद्र सिंह के बयान को हास्यास्पद, शरारतपूर्ण, गैर-जिम्मेदाराना और राजनीति से प्रेरित करार दिया है। बरागटा ने कहा कि कार्टन फैक्टरी बंद होने के पीछे वर्तमान सरकार नहीं बल्कि स्वयं वीरभद्र सिंह जिम्मेदार हैं, जिन्होंने अपने शासनकाल के दौरान जब वह मुख्यमंत्री थे तो जान-बूझकर इस फैक्टरी को बंद होने के कगार तक पहुंचाया क्योंकि फैक्टरी चलाने की उनकी कोई मंशा नहीं थी।

बागवानी मंत्री ने कहा कि सितम्बर, 2004 में वीरभद्र सिंह की सरकार ने इस फैक्टरी को लीज पर देने के लिए टैंडर आमंत्रित किए और कार्टन पर दी जा रही सब्सिडी को कम करना शुरू कर दिया और वर्ष 2007 में सब्सिडी को बिल्कुल बंद कर दिया। फैक्टरी की मरम्मत एवं रखरखाव के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए। यहां तक कि वर्ष 2007 में बिजली एवं पानी के बिल भी जमा नहीं कराए गए, जिससे तत्कालीन कांग्रेस सरकार और वीरभद्र सिंह की इस फैक्टरी को बंद करने की नीयत स्पष्ट होती है। अब इस फैक्टरी को बंद करने का दोष वर्तमान सरकार पर मढ़ना वीरभद्र सिंह की राजनीतिक चाल से अधिक कुछ भी नहीं है, जिसके लिए भी वे जाने जाते हैं।

बरागटा ने कहा कि इस फैक्टरी को बंद करने के लिए भाजपा सरकार ने अपने स्तर पर सैद्धांतिक निर्णय न लेकर सभी राजनीतिक दलों, सेब उत्पादक क्षेत्रों के विधायकों, जिनमें प्रदेश विधानसभा में विपक्ष की नेता विद्या स्टोक्स भी शामिल हैं, से इस मामले पर विस्तृत चर्चा की। सभी की यह राय थी कि घाटे में चल रही इस फैक्टरी को बंद करना ही उचित रहेगा।

बागवानी मंत्री ने वीरभद्र सिंह से सवाल किया कि अगर वह इस फैक्टरी को चलाने में इतने ज्यादा इच्छुक हैं, तो केन्द्र सरकार से इसके लिए पैकेज दिलाएं। लेकिन यदि वह केवल राजनीतिक स्वार्थपूर्ति के लिए इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं, तो यह मगरमच्छ के आंसू बहाने वाली बात है।

पैकेजिंग उत्पादन ठप के ऐलान से उद्योगपति सकते में

उद्योगों को रोजाना होगा 60 करोड़ का नुकसान

कार्यालय संवाददाता, नालागढ़

पैकेजिंग उद्योगों के उत्पादन ठप करने के ऐलान से हिमाचल प्रदेश के तमाम उद्योगपति सकते में हैं। पैकिंग मैटीरियल के अभाव में जहां तैयार माल की डिलीवरी प्रभावित होगी, वहीं उद्योगों को रोजाना इस वजह से 60 करोड़ का नुकसान भी उठाना पड़ेगा। घाटे से जूझ रही पेपर मिलों को खुद कच्चे माल के दाम बढ़ने के बाद मजबूरी में दाम बढ़ाने पड़े हैं, लेकिन यह बात पैकेजर्स को नागवार गुजरी है। उन्होंने आगे तैयार माल के दाम बढ़ाने की बजाय हड़ताल का रास्ता अख्तियार किया है। अपनी बात मनवाने को लेकर रची गई इस रणनीति से प्रदेश की हजारों इकाइयों को अच्छा खासा नुकसान झेलना पड़ेगा। पैकेजिंग उद्योगों का तर्क है कि पैकेजिंग उत्पाद यूजर उद्योग कीमतें बढ़ाने को तैयार नहीं है, जबकि यूजर उद्योगों का कहना है कि वह भी जायज ढंग से कीमतें बढ़ाने को सहमत हैं। पंजाब, हिमाचल के पैकेजिंग उद्योगों द्वारा कच्चे माल की बढ़ती कीमतों के मद्देनजर आठ मार्च से पांच दिन के उत्पादन ठप करने के ऐलान ने प्रदेश के उद्योगपतियों में खलबली मचा दी है। पहले ही कई संकटों से जूझ रहे हिमाचल के उद्योग जगत की हड़ताल की घोषणा ने और दिक्कतें बढ़ा दी हैं।

पैकेजिंग उद्योग मालिक जहां बढ़ी कीमतों को पेपर मिल मालिकों की मनमानी करार दे रहे हैं, वहीं पेपर मिल मालिक पैकेजर्स की उत्पादन ठप करने की धमकी को बेवजह उठाया कदम बता रहे हैं। पेपर मिल मालिकों व पैकेजर्स के बीचे कच्चे माल की कीमतों को लेकर उपजे विवाद के चलते पांच दिन होने वाली हड़ताल का खामियाजा प्रदेश के करीब छह हजार उद्योगों को भुगतना पड़ेगा। उत्पादन ठप रहने से पैकेजिंग उत्पाद नहीं मिलेंगे और इस वजह से हजारों उद्योगों का डिलीवरी के लिए तैयार माल गोदामों में कैद होकर रह जाएगा। तैयार माल की समय पर डिलीवरी न होने से कई उद्योगपतियों को आर्डर रद्द होने की भी आशंका है, जिससे करोड़ों का नुकसान होगा। पेपर मिल मालिकों का तर्क है कि यह उद्योग निरंतर घाटे में चल रहा है, जो वेस्ट पेपर पहले साढ़े छह रुपए किलो था, वह अब साढ़े दस रुपए किलो मिल रहा है। इसके अलावा विदेश से आने वाले वेस्ट पेपर ओसीसी व केसीबी के दाम भी 160 डालर प्रति टन से बढ़कर 260 डालर प्रति टन हो गया है। इसके अलावा वायलर आयल, केमिकल, ट्रांसपोर्ट के दाम भी निरंतर बढ़ रहे है। ऐसी परिस्थितियों में कीमतें बढ़ाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। रूपाना पेपर मिल नालागढ़ के मालिक राजेश का कहना है कि पेपर मिल पहले ही घाटे में चल रही है, अब दाम बढ़ाने के बावजूद लागत नहीं मिल पा रही। एक अनुमान के अनुसार पैकेजिंग उद्योगों में हड़ताल के चलते इस श्रेणी के उद्योगों के साथ-साथ अन्य हजारों उद्योगों को रोजाना 60 करोड़ का नुकसान होगा। हिमाचल प्रदेश कोरोगेटिड बाक्स निर्माता संघ के अध्यक्ष देवेंद्र सहगल का कहना है कि बड़े पेपर उद्योग गुट बनाकर पैकेजिंग उद्योग को बर्बाद करने पर तुले है, वहीं अचानक दाम भी बढ़ा रहे हैं। दिल्ली में हुई बैठक में फैसला लिया गया है कि एक अप्रैल से पैकिंग पेपर के दाम दो रुपए और बढ़ाए जाएंगे। इसके बाद दो माह तक कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। बीबीएन उद्योग संघ के अध्यक्ष राजेंद्र गुलेरिया ने कहा कि पैकेजिंग उद्योगों का पांच दिन उत्पादन ठप करने का फैसला गलत है। इसका सारे उद्योगों को नुकसान उठाना पड़ेगा।

आठ मार्च से पांच दिनों के लिए बंद रहेगा उत्पाद